कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति का भारत दौरा

कोरिया गणराज्य (को.ग.) के राष्ट्रपति श्री पार्क गेउन-हाई 15-18 जनवरी 2014 तक भारत के राजकीय दौरे पर आए. शिखर बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार-विमर्श किया और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का गहनता से आदान-प्रदान किया. इस बात को मान्यता देते हुए कि भारत-कोरिया गणराज्य की साझेदारी सम्मिलित मूल्यों जैसे कि लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित है. उन्होंने जनवरी 2010 में स्थापित 'रणनीतिक साझेदारी' के अनुरूप भारत- कोरिया गणराज्य के संबंधों के मजबूत विकास और विदेशी मामले, रक्षा, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा व्यक्ति-से-व्यक्ति आर्थिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के साथ-साथ वृहत क्षेत्रों में समझौते के विस्तार पर संतुष्टि व्यक्त की.

दोनों नेता सामान्य दृष्टि के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित नीति-निर्देश नियत करने पर सहमत हुए; पहला, राजनीतिक और सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक संचार चैनलों को सुदृढ़ करना; दूसरा, आर्थिक सहयोग के लिए सांस्थानिक ढांचे को समेकित करना और व्यापार तथा निवेश के और विस्तार के लिए अधिक अनुकूल स्थितियों का सृजन करना; तीसरा, सांस्कृतिक आदान-प्रदानों और व्यक्ति-से-व्यक्ति तालमेलों के विस्तार द्वारा पारस्परिक समझ को गहरा करना; और चौथा, मानव जाति की सामान्य चुनौतियों को दूर करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझेदारों के रूप में एक-दूसरे के साथ निकट सहयोग करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए संपन्नता के नए युग में प्रवेश किया जा सके.

दोनों नेताओं ने वर्गीकृत सैन्य सूचना के संरक्षण पर करार करने का स्वागत किया, जिसके लिए उन्हें विश्वास है कि यह सैन्य क्षेत्र में पारस्परिक विश्वास और सहयोग को बढ़ाने में अंशदान करेगा. दोनों नेता दोनों ओर की सशस्त्र सेनाओं के बीच आदान-प्रदान जारी रखने पर सहमत हुए. दोनों नेताओं ने संशोधित दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया और इसे शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए. वे चालू 'भारत- कोरिया गणराज्य संयुक्त निवेश संवर्धन समिति' के विस्तृत और पुनर्संरचित बदलाव के लिए मंत्रिमंडल स्तर पर 'भारत- कोरिया गणराज्य संयुक्त व्यापार और निवेश संवर्धन समिति' की स्थापना पर सहमत हुए. इसके अलावा उन्होंने बंगलोर में कोट्रा कार्यालय और नई दिल्ली में किटा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के विस्तार के लिए काम करेगा.

दोनों नेताओं ने भूमि के अधिग्रहण, एक पूर्वेक्षण लाइसेंस और पर्यावरणीय अनापत्ति के पुनः वैधीकरण सहित उड़ीसा राज्य में पॉस्को परियोजना में प्रगति के बारे में भी विचार-विमर्श किया और परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए. दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि पॉस्को शीघ्र ही परियोजना पर काम शुरू करेगा. इस बात को मान्यता देते हुए कि वर्ष 2011-2015 अवधि के लिए मंजूर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग निधि का उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कर लिया गया है. वे बड़ी परियोजनाओं, जो उद्योगों, अकादमियों और संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, के संवर्धन के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (प्रत्येक पक्ष द्वारा 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंशदान के साथ) की एक अतिरिक्त संयुक्त निधि के सृजन पर सहमत हुए, ये परियोजनाएं अनुप्रयोग और तकनीकी- वाणिज्यीकरण संबंधी अनुसंधान पर फोकस करेंगी. दोनों नेताओं की उपस्थिति में निम्नलिखित करारों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए.

(i) वर्गीकृत सैन्य सूचना के संरक्षण पर भारती गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच करार.

(ii) भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान, आईसीटी मंत्रालय के बीच और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त प्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पर कोरिया गणराज्य की भविष्य की योजना संबंधी समझौता ज्ञापन.

(iii) बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारतीय अनुसंधान विकास संगठन और कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच कार्यान्वयन करार.

(iv) नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन.

(v) वर्ष 2014-2017 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान.

(vi) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच एक करार.

(vii) दूरदर्शन और कोरिया इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (अरिरंग टीवी) के बीच सहयोग संबंधी करार पर भी हस्ताक्षर किया गया.